PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Business Bhaskar, Faridabad
Saturday 22nd February 2014, Page: 1
Width: 10.06 cms, Height: 8.96 cms, a4, Ref: pmin.2014-02-22.61.9

दवा मूल्यों पर विदेशी अधिग्रहण का असर!

महेंद्र सिंह ▸ **नई दिल्ली...**

केंद्र सरकार विदेशी दवा कंपनियों द्वारा घरेलू कंपनियों के अधिग्रहण से दवा की कीमतों और शोध एवं विकास पर होने वाले प्रभाव के बारे में एक स्टडी करा रही है। उद्योग संगठन फिक्की केंद्र सरकार के लिए यह स्टडी कर रहा है। इस स्टडी के माध्यम से सरकार यह जानना चाहती है कि अब तक कितनी दवा कंपनियों का अधिग्रहण हुआ है और दवा कीमतों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है।

डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल की सचिव आराधना जौहरी ने 'बिजनेस भास्कर' को बताया कि विदेशी दवा कंपनियों द्वारा

फिक्की की मदद से सरकार इस बारे में करा रही है स्टडी

ब्राउन फील्ड में हुए प्रमुख अधिग्रहण के असर को जानने के लिए एक स्टडी शुरू की गई है। अभी तक विदेश दवा कंपनियों द्वारा घरेलू दवा कंपनियों के अधिग्रहण को लेकर चिंता तो जताई जा रही थी, लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ है इसको लेकर कोई अधिकारिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल ने फिक्की को यह जिम्मेदारी दी है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल ने

(शेष पेज 10 पर)

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Business Bhaskar, Faridabad
Saturday 22nd February 2014, Page: 1
Width: 8.51 cms, Height: 18.67 cms, a4, Ref: pmin.2014-02-22.61.9

दवा मूल्यों पर विदेशी अधिग्रहण का असर!

फार्मा एफडीआई पॉलिसी पर अपनी राय देते हुए क्रिटिकल सेगमेंट में एफडीआई पर रोक लगाने का समर्थन किया था।

फिक्की की सीनियर डायरेक्टर शोभा मिश्रा घोष ने बताया कि हम डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल के लिए यह स्टडी कर रहे हैं। इसके तहत विदेशी दवा कंपनियों द्वारा भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण का विश्लेषण कर हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दवा कीमतों और शोध एवं विकास (आरएंडडी) पर इसका प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा दायची द्वारा रैनबैक्सी के अधिग्रहण से क्या गुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिस अपनाई गई। शोभा के मुताबिक स्टडी के तहत हम यह भी देखेंगे कि अब तक कितनी दवा कंपनियों का अधिग्रहण हुआ है और अधिग्रहण की प्रकृति किस तरह की रही है। इससे विदेशी दवा कंपनियों द्वारा घरेलू दवा कंपनियों के अधिग्रहण के असर को लेकर एक सटीक निष्कर्ष निकालने में मदद मिलेगी।

हाल ही में केंद्र सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन (डीआईपीपी) की चिंताओं को खारिज करते हुए फार्मा सेक्टर में मौजूदा एफडीआई पॉलिसी को जारी रखने की मंजूरी दी है। हालांकि पॉलिसी में नई शर्त जोड़ी गई है कि भारतीय दवा कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने वाले विदेशी निवेशक इन कंपनियों से नॉन कंपीट एग्रीमेंट नहीं कर सकेंगे। मौजूदा फार्मा एफडीआई नीति के तहत नए प्रोजेक्ट में विदेशी कंपनियां ऑटोमैटिक रूट से 100 फीसदी निवेश कर सकती हैं लेकिन मौजूदा दवा कंपनियों में निवेश पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी जरूरी होगी। इससे पहले डीआईपीपी ने विदेशी दवा कंपनियों द्वारा घरेलू दवा कंपनियों के अधिग्रहण से सस्ती जेनरिक दवाओं की उपलब्धता का संकट होने की आशंका जताई थी। इस पर अंकुश लगाने के लिए विभाग ने क्रिटिकल फार्मा सेगमेंट में एफडीआई 49 फीसदी तक सीमित रखने का प्रस्ताव किया था।

Cont'd/-